और इन योजनाओं के लागू होने से फाइनेंशियल इनक्लूज़न और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है।

सरकार योजनाओं को लागू करने का पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसके लाभ को पहुंचाने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम लाभार्थियों को इसके प्रति जागरूक करें। इस जागरूकता अभियान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे बैंकों की हो सकती है। आज हमारे देश में 1,60,000 से भी अधिक बैंक शाखाएं हैं, जिनका अस्तित्व ग्रामीण इलाकों में भी है। मेरी सरकार से माँग है कि इन सभी बैंक शाखाओं में एक डेडिकेटेड हेल्प डेस्क की स्थापना हो, जो हमारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करे और लाभार्थियों को जागरूक करे कि किस प्रकार वे भारत सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इन हेल्प डेस्क के गठन से हर नागरिक को उसका अधिकार मिलेगा और पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के विकास और अंत्योदय के लक्ष्य को भी हम प्राप्त कर सकेंगे।

THE VICE-CHAIRPERSON (MS. KAVITA PATIDAR): The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by Shri Sanjay Seth: Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Dr. Sasmit Patra (Odisha) and Shri Sujeet Kumar (Odisha).

Demand to expedite projects under Bharatmala in the State of Bihar

श्री शंभू शरण पटेल (बिहार): आदरणीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतमाला परियोजना भारत के 550 से अधिक जिला मुख्यालयों को छः लेन राजमार्गों के माध्यम से जोड़ने का कार्य हो रहा है। राजमार्गों और सड़कों के विकास के अलावा, परियोजना का एक मुख्य उद्देश्य राजमार्गों के माध्यम से माल ढुलाई दक्षता में सुधार करना है। इसके अलावा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का महत्वाकांक्षी छः लेन ग्रीनफील्ड वाराणसी-राँची-कोलकाता एक्सप्रेसवे बिहार के कैमूर, रोहताश, औरंगाबाद और गया जिलों से होकर गुजरेगा। 610 किलोमीटर लंबे वाराणसी-कोलकाता कॉरिडोर में से 162 किलोमीटर बिहार में होगा।

केंद्र सरकार ने पटना में एनएच 30 पर अनीसाबाद से गुरुद्वारा मोड़ तक 1,000 करोड़ रुपये की लागत से 15 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड बनाने का भी फैसला किया है।

वर्तमान में बिहार के कई जिलों में पुलों का निर्माण किया जा रहा है और केंद्र सरकार ने इन कार्यों को लिए 23,157 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके अलावा, फतुहा, पटना में 100 एकड़ भूमि पर पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास के लिए काम किया जा रहा है। केंद्र ने इसके लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है।

महोदय, आपके माध्यम से माननीय केंद्रीय मंत्री जी से आग्रह है कि बिहार में अधिकांश जिले आकांक्षी हैं, इसीलिए इन सभी परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाई जाए, ताकि बिहार में विकास जल्द हो और एनएच के दोनों तरफ जो अतिक्रमण है, उसे हटाया जाए। एनएच पर सोलर लाइट का भी इंतजाम किया जाए, जिससे कि एनएच पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम किया जा सके।

THE VICE-CHAIRPERSON (MS. KAVITA PATIDAR): The hon. Member, Dr. Sasmit Patra (Odisha), associated himself with the Special Mention made by the hon. Member, Shri Shambhu Sharan Patel.

Now, Shri P. Wilson. Concern over energy security projects in Tamil Nadu.

Concern over energy security projects in Tamil Nadu

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): TANGEDCO, the Tamil Nadu State Power Utility, has initiated the development of a 2x800 MW Super Critical Thermal project at Uppur in Ramanathapuram District. Similarly, the 1,320 MW Udangudi Stage-I is nearing completion, with potential for further development of 2,640 MW through Udangudi Stage II & III. The State Government has granted administrative approval. Existing coal handling infrastructure, including a coal jetty and closed conveyor systems, are in place for all three stages.

Considering that the development of in-State projects is vital for the growth, it is proposed by state that NTPC and NLC undertake further development of these projects with an estimated cost of ₹30,000 crores. The electricity generated could be utilized by Tamil Nadu and other southern states, as the capacity of existing transmission lines is nearly maxed out, and establishing new lines could take 8-10 years.

Enabling these projects by NTPC and NLC will enhance the energy security of Tamil Nadu and other southern states. Additionally, the power demand in Tamil Nadu is increasing at a higher rate compared to other states, expected to cross a peak demand of 21,000 MW by 2025-26. Presently, Tamil Nadu receives only 55 per cent of power from Units I and II of the Kudankulam Nuclear Power Plant (KKNPP), roughly 1,150 MW. With Units III and IV expected to be completed by 2025, it is urged that 100 per cent allocation from Unit III and IV be granted to Tamil Nadu to meet the growing demand and make State of Tamil Nadu without power cuts.

THE VICE-CHAIRPERSON (MS. KAVITA PATIDAR): The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by hon. Member, Shri P. Wilson: Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri M. Shanmugam (Tamil Nadu), Shri A.A. Rahim (Kerala), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), and Dr. V. Sivadasan (Kerala).

Now, Dr. Ashok Kumar Mittal. Concern over attacks by stray animals in the country.